

न्यूज़ इन शॉर्ट

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पूर्वोत्तर रीजन की अहम भूमिका

नई दिल्ली, एजेंसी। ज्योतिरादित्य सिधिया ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में पूर्वोत्तर राज्यों की अहम भूमिका होगी। 'राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट' के उद्घाटन समारोह में बोलेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम 'हमारे अद्भुत 'आठ लक्ष्मी'- आठ राज्यों को प्रदर्शित करेगा।' केंद्रीय मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प, प्रतिबद्धता और उनका विजन यह सुनिश्चित करना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भविष्य के विकास और भारत के भविष्य के मार्ग का केंद्र बने, क्योंकि देश 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।" सिधिया ने कहा कि सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 10 प्रतिशत (लगभग एक लाख करोड़ रुपए) प्रति वर्ष पूर्वोत्तर को दिया जाता है।

भारत आईवियर सेक्टर के लिए ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग और निर्यात केंद्र बन सकता है: गोयल

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लेंसकार्ट के सह-संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल से मुलाकात की। इस मुलाकात में इस बात पर चर्चा की गई कि भारत आईवियर सेक्टर के लिए कैसे निर्यात का केंद्र बन सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि उन्हें कंपनी को प्रभावशाली सामाजिक पहलों के बारे में जानकर खुशी हुई। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, 'लेंसकार्ट के सह-संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल से मुलाकात की और चर्चा की कि भारत आईवियर के लिए वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र कैसे बन सकता है।'

डीआरडीओ ने तटरक्षक बल के लिए विकसित की समुद्री जल से नमक हटाने की स्वदेशी तकनीक

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एक बड़ी खोज की है। इस खोज के तहत डीआरडीओ ने विलवणीकरण यानी समुद्री जल से नमक निकालने की स्वदेशी प्रक्रिया विकसित की है। इस प्रि या का लाभ विशेष रूप से भारतीय तटरक्षक बल (आईसीबी) के जहाजों को मिलेगा। डीआरडीओ ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोस मल्टीटेयरड पॉलीमरिक छिन्नी को तैयार किया है। डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला, रक्षा समूची भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी (डीएसएसआरडीई) ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीबी) के जहाजों में विलवणीकरण संयंत्र के लिए यह प्रौद्योगिकी विकसित की है।



श्रीनगर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 'पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद, पीओके पर होगी'

नई दिल्ली, एजेंसी। 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित बादामी बाग कैंट पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के जवानों से बातचीत की और उन्हें संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं आज आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूँ, जिसने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में हताहत हुए सैन्य निर्दोष नागरिकों और 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को नमन करता हूँ। मैं घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूँ और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों।

नक्सलमुक्त भारत में हमारा अभियान सही दिशा की ओर: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। कर्रंगुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों ने महज 21 दिनों में 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सुरक्षा बलों की सफलता दर्शाती है कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में पीएम मोदी ने एक्स पर कहा,

गलगम में मुख्यमंत्री साय ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा-

आपके शौर्य और निष्ठा से ही नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई को हम जीत रहे हैं

विजय मत, रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बीजापुर जिले के उरूप तहसील के अंदरूनी गांव गलगम पहुंचे, जहाँ उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर हालिया नक्सल विरोधी अभियान की सफलता पर चर्चा की। इस अभियान में सुरक्षा बलों ने करंगुड़ा की पहाड़ी पर 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 कुख्यात माओवादी आतंकियों को मार गिराया और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। मुख्यमंत्री साय ने इस अभियान को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री साय ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारे के उद्घोषन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने अदम्य साहस और समर्पण के साथ इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। यह न केवल बीजापुर बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। गलगम और करंगुड़ा का क्षेत्र लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है और इस अभियान ने इस इलाके को सुरक्षित बनाने की दिशा में नई उम्मीद जगाई है। सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात के दौरान साय ने उनके साहस की सराहना की और कहा कि आपके शौर्य और निष्ठा से ही हम नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई को जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमें सरकार में आए डेढ़ साल हुए हैं और इस अवधि में हमने राज्य में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आप लगातार अनेक कठिन नक्सल विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। आप 44 डिग्री की गर्मी में भी ऑपरेशन चलाते हैं। ऐसे जवानों के अदम्य साहस को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने बताया कि वे सुरक्षा कैम्प को सुविधा कैम्प मानते हैं क्योंकि सुरक्षा कैम्प के माध्यम से अब बस्तर के सुदूर इलाकों में अनेक तरह की सुविधाएं पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री साय के कहा कि जब हमारी सरकार आयी तो इस क्षेत्र में सबसे पहला कैम्प मूलैर में खोला गया। आज मूलैर समेत आसपास के गांव में राशन की सुविधा, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल, मोबाइल टॉवर जैसी सुविधाएं



मिलने लगी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नक्सल विरोधी अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। राज्य में मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य है, निश्चित रूप से फोर्स के जवानों के अदम्य साहस की बदौलत हम इस संकल्प को पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा बस्तर में नियद नेल्ल नार योजना ने स्थानीय लोगों से जुड़ने में अहम भूमिका निभाई है।

अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्रामीण हितग्राहियों से भी मुलाकात की और उन्हें राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का वितरण करते हुए पीएम आवास योजनातर्गत स्पेशल प्रदान किया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों को और अधिक तेज गति से करेगी साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य है, और इसके लिए सुरक्षा बलों के साथ-साथ स्थानीय समुदायों का सहयोग भी जरूरी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि ग्रामीण मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसके साथ ही, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए मुठभेड़ में जैश के तीन आतंकवादी ढेर

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र शासित प्रदेश में 48 घंटे के भीतर यह दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले श्रीनगर मुख्यालय सेना की 15वीं कोर ने एक्स पर कहा, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ द्वारा नांदर, त्राल, अवंतोपोरा में एक

कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सुरक्षाबलों द्वारा एक अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादियों को मार गिराने के दो दिन बाद हुई है। पुलवामा जिले के अवंतोपोरा सब-डिवीजन के त्राल इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई थी।



शाबाश! ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना जम्मू कश्मीर पहुंच कर आर्मी चीफ ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला

नई दिल्ली, एजेंसी

इंडियन आर्मी चीफ जनरल उषेंद्र द्विवेदी गुरुवार को जम्मू-कश्मीर पहुंचे और श्रीनगर, उी और ऊंची बासी की फॉरवर्ड पोस्ट में सैनिकों से मिले। जनरल उषेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों से कहा- शाबाश। ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी के सैनिकों की वीरता और पेशेवर दक्षता को



सलाम करते हुए जनरल उषेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन में शामिल सैनिकों से वन टू वन बातचीत की। असाधारण प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से बधाई थी और उनका उत्साह बढ़ाया।

विजयमतएंकर समय सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति

संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार यह फैसला किया

नई दिल्ली, एजेंसी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2025 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ। अब राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह फैसला दे सकता है।



सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में की थीं अहम टिप्पणियां

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समयसीमा तय करने जैसे विषयों पर स्पष्टीकरण मांगा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में दिए अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पारर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर तय समयसीमा में फैसला नहीं लिया जाता तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी।

राज्य शासन ने कलेक्टरों को लिखा पत्र

रियायती लीज दर पर सार्वजनिक उपक्रमों, तेल और गैस विपणन कंपनियों को दी जाएगी जमीन

विजय मत, रायपुर

राज्य शासन ने जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए नगरीय निकायों में स्थापित किये जाने वाले बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि का आबंटन किया जाना है। बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगरीय निकाय को अधिकृत किया गया है।

राज्य शासन ने नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगरीय निकाय को अधिकृत किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं शासकीय तेल और गैस विपणन कंपनियों को बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए अधिकतम दस एकड़ शासकीय भूमि का आबंटन रियायती लीज दर एक रुपए प्रति वर्गमीटर के मान से करने के लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया है। विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं शासकीय तेल और गैस विपणन कंपनियों को अधिकतम 25 वर्षों की लीज पर भूमि आबंटित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

सीजी बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को मिलेगा एक और मौका जुलाई में होगी 10-12वीं बोर्ड की दूसरी परीक्षा फेल-अबसेंट और ग्रेड सुधारने का मौका

विजय मत, रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों को सेकेंड चान्स देने का बड़ा फैसला लिया है। अब जो छात्र मार्च 2025 में हुई पहली मुख्य परीक्षा में फेल हो गए थे, परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे या फिर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, वे सभी जुलाई में होने वाली सेकेंड मेन एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू की गई है। जिसके अनुसार अब एक शैक्षणिक सत्र में छात्रों को दो बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलता है। यानी अगर कोई छात्र पहली बार में सफल नहीं हो पाया, तो साल के बीच में ही दोबारा परीक्षा देकर पास होने या बेहतर अंक लाने का मौका पा सकता है। दूसरी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मई के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पिछली बार हुई दूसरी परीक्षा में करीब 82,000 छात्र शामिल हुए थे। इस बार यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।

आवेदन करने की महत्वपूर्ण तारीखें
सामान्य शुल्क के साथ: 20 मई 2025 से 11 जून 2025 तक
विलंब शुल्क के साथ: 12 जून 2025 से 20 जून 2025 तक
विशेष विलंब शुल्क के साथ: 21 जून 2025 से 30 जून 2025 तक

मुस्लिम पुरुष चार शादियां करें लेकिन जब वह सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सकें

इलाहाबाद, एजेंसी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों के एक से अधिक शादी करने पर की अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी तभी करनी चाहिए, जब वह सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सकें। कुरान में खास वजहों से बहु विवाह की इजाजत की गई है। लेकिन, पुरुष इसका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं।

हाईकोर्ट ने मुरादाबाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष को दूसरी शादी करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है। जब तक वह सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार निभाने की क्षमता न रखता हो।

कंठी घाट पर बारातियों से भरी बस खाई में गिरी, 3 की मौत; 63 घायल

विजय मत, ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर जिले के कंठी घाट पर गुरुवार दोपहर बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस खाई में गिर गई। हादसे में 3 बारातियों की मौत हो गई, जबकि महिला-बच्चे समेत 63 लोग घायल हैं। वहीं, गंभीर रूप से घायल 7 बारातियों को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। घटना बलरामपुर थाना क्षेत्र की है।



गुरुवार को करीब 70 से 80 ग्रामीण बस में सवार होकर बारात के लिए निकले थे। इसी दौरान चांदो थाना क्षेत्र के कंठी घाट पर बस बेकाबू होकर लुढ़कते हुए खाई से नीचे दूसरे

सड़क पर गिर गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। बस में सवार महिला महंती पति हेमंत (27) और मांदुर पिता सीताराम (18) की मौके पर मौत हो गई। दोनों बस के अंदर ही दब गए थे। पुलिस ने जेसीबी की मदद से बस को उठाकर उन्हें बाहर निकाला। घटना की सूचना पर चांदो पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को चांदो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बलरामपुर पहुंचने पर ममेश बड़ा (12) की मौत हो गई। बच्चा गोपालपुर से शादी में आया था।

घायलों का इलाज जारी...

बलरामपुर के सीएमएचओ डॉ. बसंत सिंह ने बताया कि हॉस्पिटल में 56 घायलों को लाया गया है। जिनमें से 7 घायलों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज यहीं किया जा रहा है।

7 की हालत गंभीर, अंबिकापुर रेफर

वहीं, हादसे की सूचना पर बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सीएस डॉ. सीएस शशांक गुप्ता, सीएमएचओ डॉ. बसंत सिंह समेत डॉक्टरों की पूरी टीम घायलों के इलाज में जुट गई।

ट्रंप के ‘जीरो टैरिफ’ बयान के बाद शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 1200 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,000 का पार

नई दिल्ली, एजेंसी

हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार (15 मई) को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह 500 से ज्यादा अंक की गिरावट के बाद अब सेंसेक्स 1000 अंक उछला है। निफ्टी ने भी



385 अंक की तेजी है, ये 25,052 के स्तर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका को एक व्यापार समझौता

प्रस्तावित किया है, जिसमें अमेरिकी वस्तुओं पर लगभग शुन्य शुल्क+ लगाने की बात कही गई है। इस घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। इस खबर के प्रभाव से बीएसई सेंसेक्स में 1200 अंकों से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, जबकि एनएसई निफ्टी भी 385 अंकों से अधिक चढ़ गया।

महिला से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अंजलि सिंह, पूर्वी दिल्ली, नांगलाई निवासी होना बताया एवं पहचान हेतु अंजलि सिंह के नाम से आधार कार्ड प्रस्तुत की। आधार कार्ड की जांच की गई तो प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद पाया गया। महिला से बारीकी से लगातार पूछताछ करने पर उसने अपना मूल नाम पन्ना बीवी पिता अब्दुल रफ उम्र लगभग 25 वर्ष मूल निवासी वैधीरपार, दौलतपुर फुलवारी गेट, पोस्ट बादामतला सिरामोनी जिला खुलना बांग्लादेश का होना बताया। जांच के दौरान पाया गया कि पन्ना बीवी लगभग 08 वर्ष पूर्व बिना वैध पासपोर्ट एवं वीजा के अवैध रूप से बांग्लादेश से बोंगांव पेट्रोलपोस्ट जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल स्थित भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर कोलकाता आकर अपना नाम काकोली घोष बता कर सोनागाछी में लगभग 5 वर्ष अवैध रूप से रही, वहां से दिल्ली में लगभग 1 वर्ष रही।

बताया कि इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः सज़ा न लेते हुए पुलिस को चार घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस ने आठ घंटे की देरी से कारवाई की। जिससे सरकार की नीयत पर संदेह होता है। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि अब विजय शाह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह भाजपा की तरफ से उद्धरण बचाने की एक सोची-समझी कोशिश प्रतीत होती है।

लेकिन अब इसकी वैज्ञानिकता लोगों ने इसकी उपयोगिता को एक सौ गुना बढ़ा दिया है।

टीम संयोगकर हिमांशु तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 'चिन्हित 12 वृद्ध महिलाओं को' देसी फ्रिज यानी कि मटके वितरण किया गया है निश्चित रूप से इस देसी फ्रिज से इस भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझा सकेंगे।

कर अपील पंचाट (सीईएसटीएटी) में चुनौती दी है। उसका कहना है उत्पाद का वर्गीकरण उद्योग के मानदंड के अनुरूप है और अधिकारियों ने पहले इस पर सवाल नहीं उठाया था। ऐसे ही एक अलग मामले में नौकिया को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिली थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी में नौकिया को 'खिलाफ एंडावॉस रूलिंग' अर्थात् रीट के आदेश को खारिज कर दिया था। अर्थात् रीट ने इसमें 'स्मॉल फॉर्म' फैक्टर प्लागएबल (एसएफपी) ट्रांसीवर को पूरा दूरसंचार उपकरण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहा था जिस पर 20 फीसदी शुल्क लगाया जाता है। मगर अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एसएफपी को अपेक्षित नहीं बल्कि नेटवर्क का हिस्सा है और उन्हें उच्च वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत करना सही है जिन पर शून्य सीमा शुल्क लगाया है। घटनाक्रम के जानकार एक सरकारी अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, 'इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप उच्चस्तरीय अत्याधुनिक दूरसंचार उपकरण उत्पादन के लिए आवश्यक वास्तविक उपकरणों पर शून्य शुल्क बनाए रखना है।'

